श्री बंशीधर नगर बुधवार
10.06.2026
अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष दशमी संवत 2084
वर्ष : 04, अंक : 287

सूर्योदय-सूर्यास्त

उदय - 05:08 बजे
अस्त - 06:35 बजे

तापमान

अधिकतम : 43 डिग्री से.
न्यूनतम : 28 डिग्री से.

बंशीधर न्यूज

कलम है, तो आवाज़ बुलंद है...

डिजिटल अखबार www.banshidharnews.com लंबित मामलों का जल्द करें निष्पादन : डीसी >> पेज 03 श्रद्धा की 'ईथा' की रिलीज डेट आई सामने >> पेज 05

सुविचार

देना एक विकल्प है। सम्मान एक विकल्प है। आप जो भी विकल्प चुनेंगे, वह आपको बनाएगा। बुद्धिमानी से चुनें।

न्यूज अपडेट्स

झारखंड में 13 से 15 जून के बीच दस्तक देगा मानसून

रांची। झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून के 13 से 15 जून के बीच पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अनुकूल परिस्थितियां बनी रहीं तो अगले कुछ दिनों में झारखंड में इसकी एंट्री हो जाएगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून झारखंड के अलावा मध्यवर्ती अरब सागर के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष क्षेत्रों तथा दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के अन्य भागों में भी आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग लगातार इसकी प्रगति पर नजर बनाए हुए है। उधर, मानसून के आगमन से पहले राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों को दिनभर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की पेयजल विभाग की योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा

हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएं : हेमंत

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं और कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस लक्ष्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के रख-रखाव और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ी योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संभावित पेयजल संकट

वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाए और जहां भी जलापूर्ति की समस्या सामने आए, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य की जल सहियाओं को समूहवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्लंबर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल सहियाओं को खराब चापाकलों की मरम्मत, सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं की देखरेख तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान और पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। हेमन्त सोरेन ने विभाग की निमार्णाधीन बड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों का व्हाट्सएप समूह बनाया जाए, जिसमें प्रतिदिन कार्य प्रगति की जानकारी साझा की जाए। इससे योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी और कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाएं सीधे जनता के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए इन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए ठोस और परिणामोन्मुखी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत कार्य ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान विकसित किया जाए और योजनाओं के पूरा होने के बाद शीघ्र उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वाटर रिचार्ज के लिए सोक पिट और अन्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहरी क्षेत्रों की तरह गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने राज्य में जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्द्धन को लेकर भी विशेष चिंता व्यक्त की और वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तथा भू-जल स्तर बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर गिरने के कारण अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे वर्षा जल का संचयन होगा और भू-जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने सोक पिट निर्माण के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा घरों और संस्थानों से निकलने वाले बेकार पानी के संचयन की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में जल गुणवत्ता की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसलिए केवल पाइपलाइन से जलापूर्ति ही नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण कार्यक्रम, जल जांच किट की उपलब्धता, हर घर जल योजना की प्रगति, वित्तीय कार्ययोजना, बहु-ग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, नलकूप योजनाओं, कल्याण विभाग मद की योजनाओं तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय, ओडीएफ प्लस गांव, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा गोबरधन योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का प्रत्येक परिवार सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

झारखंड हाई कोर्ट का 'टू-फिंगर टेस्ट' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश

रेप पीड़िताओं के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा-छात्रवृत्ति

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन हिंसा और बलात्कार पीड़िताओं के अधिकारों की सुरक्षा, त्वरित न्याय, पुनर्वास और मुआवजा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और संबंधित विभागों के लिए 19 अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह मामला यौन हिंसा पीड़िताओं की सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित था। मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) के रूप में अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें न्यायालय ने अपने आदेश का हिस्सा बनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है

कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बलात्कार एवं यौन हिंसा पीड़िताओं के मेडिकल परीक्षण के दौरान किए जाने वाले टू फिंगर टेस्ट पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन पेशेवर कदाचार माना जाएगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 173 के तहत राज्यभर में जीरो एफआईआर की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यौन अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को राज्य के सभी वन स्टॉप सेंटरों की कमियों को दूर करने तथा उनकी नियमित निगरानी के लिए महिलाओं की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रांची स्थित नारी निकेतन (शक्ति सदन) को यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह के रूप में उपयोग करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वहां रहने की कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं होगी और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार को सभी आश्रय गृहों और पुनर्वास केंद्रों की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का भी निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो बलात्कार से जन्मे बच्चों की शिक्षा और कल्याण की निगरानी करेगा। ऐसे बच्चों को कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होता है, तो उसे छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

पलामू प्रमंडल में यात्री बस से सफर करना हुआ महंगा, 18 प्रतिशत बढ़ाया किराया

रांची के लिए नन-एसी किराया 350 रु., एसी 425 रु.

मेदिनीनगर। पलामू जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बढ़े. हुए किराएकी नई सूची जारी कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए पलामू जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि बढ़े हुए किराया की सूची उपायुक्त और सदर एसडीएम को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11 जून से किराया वसूल किए जाएंगे।
एसोसिएशन के सचिव सत्येंद्र सिंह उर्फ मंगल सिंह ने बताया डालटनगंज से रांची का किराया 300 की जगह अब 350, रूपए और एसी बस का कराया 425 रुपए लिए जाएंगे। चंदवा के लिए 160 की जगह अब 185, लातेहार 112 की जगह अब 130, मनिका 70 की जगह अब 80, सतबरवा के लिए 50 की जगह अब 58 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह डालटनगंज से लेस्लीगंज 32 की जगह अब 37, पांकी 80 की जगह अब 92, लोहरसी 93 की जगह अब 107, बहेरा 96 की जगह अब 110 रुपए वसूल

किए जाएंगे। इसी तरह डालटनगंज से पाटन 50 की जगह 58, नावाजयपुर 70 की जगह 80, किसुनपुर 52 की जगह 60, मनातू 105 की जगह 120, चक 122 की जगह 140, बगेईया 80 की जगह 92 रुपए किराया वसूल किए जाएंगे।
इसी तरह डालटनगंज से छतरपुर 80 की जगह 92, जपला 131 की जगह 150, हैदरनगर 142 की जगह 163, हरिहरगंज 122 की जगह 140, अम्बा 135 की जगह 155, औरंगाबाद 170 की जगह 195, डेहरी 215 की जगह 248, सासाराम 245 की जगह 282 रुपए किराया वसूल किए जाएंगे। इसी तरह डालटनगंज से कुटमु 35 की जगह 40, बरवाडीह 52 की जगह 60 डालटनगंज से मंडल 105 की जगह 121, बेतला 45 की जगह 52, छिपादोहर 70 की जगह 80, गारु 100 की जगह 115, महुंआडांड 182 की जगह 210, चटकपुर 200 की जगह 230, नेतरहाट 250 की जगह 287 रुपए भाड़ा लिए जाएंगे।
इसी तरह डालटनगंज से पंड़वा 30 अब 35 रेहला 61 अब 71 गढ़वा 84 अब 96, पांडू 101 अब 116, कजरू 108 अब 124, उंटारी 122 अब 140, नगर 150 अब 172 रुपए लिए जाएंगे। डालटनगंज से नगर भाया शाहपुर 133 अब 153, भवनाथपुर 184 अब 212, डालटनगंज से खरौंधी 227 अब 261, डालटनगंज से खरौंधी भाया शाहपुर 210 अब 242, केतार 212 अब 244, केतार भाया शाहपुर 194 अब 223, पाचाडुमर 220 अब 253, डालटनगंज से पाचाडुमर भाया शाहपुर 201 अब 231, करीवाडीह 238 अब 274 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह डालटनगंज से गढ़वा भाया शाहपुर 61 अब 71, बेलहारा 131 अब 151, बेलहरा से गढ़वा 84 अब 97, जपला 32 अब 37, ऊंटारी 56 अब 65, गढ़वा से पांडू 70 अब 80, कजरू 80 अब 92, डालटनगंज से पिपरा 131 अब 150 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह डालटनगंज से पटना 350 अब 400, डालटनगंज से रांची (वातानुकूलित) 350 अब 425, डालटनगंज से लातेहार 150 अब 185 रुपए लगेंगे। पलामू जिला ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिन जगहों का किराया अंकित नहीं किया गया है वहां पुराने किराया में 15 से 20 प्रतिशत बढ़ा कर राशि ली जाएगी।

रेजिडेंट कमिश्नर ने झारखंड भवन का किया औचक निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा

रांची। झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन, वसंत विहार का मंगलवार को औचक निरीक्षण कर भवन की विभिन्न व्यवस्थाओं एवं सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, स्वच्छता, रसोई संचालन तथा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। राजकमल ने भवन परिसर, अतिथि कक्षों, कॉमन एरिया और रसोईघर का निरीक्षण कर रखरखाव एवं संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर भवन संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा स्वच्छता, समयबद्ध रखरखाव और अतिथि सेवाओं की गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट कमिश्नर ने भवन परिसर में उपलब्ध पार्किंग स्थल के बेहतर उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए लंबे समय से खड़े छह अनुपयोगी एवं कंडम वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि पार्किंग क्षेत्र का अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कार्यालयी स्थान के बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई तथा उपलब्ध संसाधनों के कार्यकुशल एवं सुव्यवस्थित उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तत्काल मरम्मत कर पुनः क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए, ताकि भवन की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। इस निरीक्षण के दौरान अरवा राजकमल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित झारखंड भवन राज्य का प्रतिनिधि संस्थान है। इसलिए यहां आने वाले अतिथियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार एवं आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है, ताकि आगंतुकों और अतिथियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधाजनक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

न्यूज अपडेट्स

सीसीएल की लाडली योजना से जेईई एडवांस में तीन छात्रों ने मारी बाजी

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत संचालित सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली योजना के तीन विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड-2026 में सफलता हासिल कर राज्य और संस्थान का नाम रोशन किया है। यह जानकारी सीसीएल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञपप्ति में दी गई। प्रेस विज्ञपप्ति में बताया गया कि वर्ष 2024-26 बैच से जुड़े प्रतिभाशाली छात्र आयुष कुजूर ने एसटी श्रेणी में 1242 वीं रैंक, माही प्रिया प्रसाद ने ओबीसी श्रेणी में 11173 वीं रैंक और मेघा कुमारी ने एसटी श्रेणी में 3673 वीं रैंक प्राप्त की है। तीनों विद्यार्थी साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी सफलता कठिन परिश्रम, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास का परिणाम मानी जा रही है। सीसीएल प्रबंधन ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सीसीएल के अनुसार, यह सफलता शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की प्रतिबद्धता और सामाजिक दायित्वों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है। प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में भी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।

एसआईआर ▶ एसआईआर में तेजी लाएं : के रवि कुमार

बूथों पर बीएलए-2 नियुक्त करें राजनीतिक दल

रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को सफल बनाने में बीएलए-2 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर विधानसभावार प्राप्त बीएलए-2 की संख्या से अवगत कराया है। राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त बीएलए-2 की विवरणी संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) को उपलब्ध कराई गई है। जारी सूची के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 21,645 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं। इसके बाद कांग्रेस द्वारा 17,479, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा 14,482, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) पार्टी द्वारा 2,967, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा 2,765 तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा दो बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं। के. रवि कुमार ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अपने-अपने बीएलए-2 की नियुक्ति अवश्य करें, ताकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा तैयार की जाने वाली अनुपस्थित (एब्सेंट), स्थानांतरित (शिफ्टेड), मृत (डेथ) तथा डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन संबंधित बीएलए-2 के माध्यम से किया जाना है। इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ के सहयोग के लिए राजनीतिक दलों के बीएलए-2 की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई है, जो सराहनीय है। सीईओ ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि जिन मतदान केंद्रों पर अभी तक बीएलए-2 नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहां भी शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावी और व्यापक जनसहभागिता के साथ संपन्न हो सके।

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि

रांची। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर मंगलवार को झारखंड विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने विधानसभा परिसर में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने शोषण, अन्याय और दमन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग दिखाया तथा समाज को स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में ही बिरसा मुंडा की अद्भुत नेतृत्व क्षमता और जनजागरण ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी थी।उन्होंने कहा कि 9 जून का दिन झारखंड के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने रांची जेल में अंतिम सांस ली थी। उनका बलिदान और संघर्ष आज भी समाज को प्रेरित करता है और जनजातीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा।

राज्यस्तरीय कृषि मेले का आयोजन आगामी 16 से 18 जून तक : शिल्पी

रांची। झारखंड में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से आगामी 16 से 18 जून तक पहली बार राज्यस्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को मेले की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेले में निवेश और कृषि उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आम लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभाग को उम्मीद है कि यह आयोजन कृषि निवेश, उत्पादन वृद्धि और युवाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। बैठक में मंत्री ने कहा कि यह आयोजन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि मेले में आने वाले प्रत्येक किसान को नई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। किसान सीधे विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही अत्याधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत कृषि पद्धतियों और कृषि आधारित उद्यमिता से जुड़े मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में देशभर के 50 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री से मिले कृषि विभाग के सचिव, मेले के लिए किया आमंत्रित

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक पी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 16 जून से 18 जून 2026 तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले झारखंड कृषि व्यापार मेला-2026 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन का नतीजा : झारखंड के सिमडेगा के आमों की मिठास पहुंची सात समंदर पार

आम्रपाली आम की पहली खेप लंदन के लिए रवाना

रांची। झारखंड के सुदूरवर्ती जिले सिमडेगा ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन का नतीजा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उपजे उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम की पहली व्यावसायिक निर्यात खेप यूनाइटेड किंगडम (लंदन) के लिए रवाना कर दी गई है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि यह ऐतिहासिक सफलता उस नीति की परिणति है, जिसकी नींव कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में मुख्यमंत्री ने रखी थी। जब गांवों में रोजगार का संकट था, तब ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फलदार बागवानी से जोड़ने वाली बिरसा हरित ग्राम योजना (बीएचजीवाई) की शुरूआत की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक सिर्फ सिमडेगा जिले के 12,000 से अधिक किसानों ने लगभग 10,500 एकड़ भूमि पर मुख्य रूप से आम्रपाली, मल्लिका और लंगड़ा आम की बागवानी की। आज उसी सामूहिक मेहनत का मीठा फल वैश्विक बाजार के रूप में सामने आया है। पिछले वर्ष सिमडेगा में आम का बंपर उत्पादन हुआ था, लेकिन मार्केट लिंकेज की कमी के कारण किसान स्थानीय बाजार में औने-पौने दाम पर आम बेचने को विवश थे। इस वर्ष जिला प्रशासन ने लगातार बायर्स-सेलर्स मीट आयोजित कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के तकनीकी सहयोग से सिमडेगा के आमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया। निर्यात के लिए जरूरी 'फायटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स' को पूरा करने के लिए महिला किसानों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। सिमडेगा जिले में वर्तमान में 7,500 सखी मंडल सक्रिय हैं, जिनसे 93,000 महिलाएं जुड़ी हैं। आम बागवानी से जुड़ी इन महिलाओं को जिला प्रशासन ने व्यापार की नई दिशा दी है। प्रारंभिक तौर पर 06 एफपीओ के 300 किसान इस एक्सपोर्ट चेन से जुड़े हैं। इस पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप (1.32 टन) के लिए सिमडेगा सदर प्रखंड की 'महिला जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' और बानो प्रखंड की 'बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' ने मुख्य भूमिका निभाई।

81 टन का बड़ा लक्ष्य, अब यूरोप की बारी

अकेले सिमडेगा ने इस सीजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 81 टन आम बेचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी हफ्ते आम की एक और खेप यूके के लिए और दूसरी खेप यूरोप के लिए भेजी जाएगी। इसके साथ ही घरेलू कॉर्पोरेट बाजार को मजबूत करने के लिए 'रिलायंस मार्ट' के साथ भी सफल लिंकेज स्थापित किया गया है। आने वाले दिनों में जिले से रागी और इमली के निर्यात की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सिमडेगा की इस सफलता के पीछे बिरसा हरित ग्राम योजना का राज्यव्यापी नेटवर्क है, जिसने पूरे झारखंड के ग्रामीण परिदृश्य को बदल दिया है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब तक राज्य का 1.86 लाख एकड़ का एक बड़ा हिस्सा बागवानी पौधारोपण के दायरे में आ चुका है, जिससे 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर स्थायी आजीविका और रोजगार मिला है। योजना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किए गए पौधारोपण में से 52,000 एकड़ क्षेत्र अब पूरी तरह फल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है।

प्लस टू उच्च विद्यालय का खेल मैदान झूलन मेला और मीना बाजार को लेकर चर्चा में

बंशीधर न्यूज

रमना : प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय का खेल मैदान इन दिनों झूलन मेला और मीना बाजार को लेकर चर्चा के केंद्र में है। मैदान में मेले के आयोजन से छात्रों के खेलकूद और अभ्यास प्रभावित होने व कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समीप रात्रि में आयोजन करने की शिकायत सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। छात्र-छात्राओं ने खेल गतिविधियों के लिये मैदान उपलब्ध कराने की मांग उठाई, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने मामले में संज्ञान लिया। जिप अध्यक्ष ने विद्यालय के खेल मैदान पहुंचकर छात्रों, मेला आयोजक और विद्यालय प्रबंधन से जानकारी ली तथा प्राचार्य को पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर कई लोगों ने विद्यालय के खेल मैदान के व्यावसायिक उपयोग तथा परिसर के आसपास पाई जा रही आपत्तिजनक सामग्रियों को लेकर भी सवाल उठाये हैं। उधर मेले का उद्घाटन प्रमुख करुणा सोनी, मुखिया दुलारी देवी सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किये जाने तथा जिप अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद इंटरनेट मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे सांस्कृतिक आयोजन बता रहे हैं। जबकि विरोध करने वाले खेल मैदान की उपयोगिता और नियमों के पालन का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे क्षेत्र में शिक्षा, खेल और सार्वजनिक उपयोग के बीच संतुलन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

न्यूज अपडेट्स

बिरसा मुंडा के 126वें शहादत दिवस पर उन्हें किया गया नमन

मेदिनीनगर: बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के जिला कार्यालय में महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक एवं आदिवासी अस्मिता के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष उदय राम ने की। मोर्चा अध्यक्ष उदय राम ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के शोषण, दमन, अन्याय, महाजनी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और उन पर थोपे जा रहे अन्यायपूर्ण करों का उन्होंने डटकर विरोध किया तथा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अन्याय के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उदय राम ने कहा कि 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने मातृभूमि और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अतुलनीय है। यही कारण है कि जनजातीय समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने समाज में समानता, स्वाभिमान और शोषणमुक्त व्यवस्था की स्थापना का सपना देखा था। कार्यक्रम में रविकांत कुमार, नीरज कुमार, सुधांशु कुमार, विशाल कुमार, आर्यन कुमार, कृष्णा राम, जयपाल मोची एवं संजय मिस्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए धरती आबा के योगदान को याद किया। कार्यक्रम के अंत में रामनरेश महतो ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पलामू युवाओं के स्वरोजगार में बाधा न बनें बैंक

लंबित मामलों का जल्द करें निष्पादन : डीसी

बंशीधर न्यूज

मेदिनीनगर : पलामू जिले में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक समय पर पहुंचे, इसके लिए बैंकों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना होगा। बिना ठोस एवं तकनीकी कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। यह निर्देश डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 75 लक्ष्यों के विरुद्ध 91 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं, लेकिन अब तक केवल चार मामलों को ही स्वीकृति मिली है। इस धीमी प्रगति पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए बैंक अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने और स्वीकृत लाभुकों के खातों में शीघ्र राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिले में अब तक 909 आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीसी ने बैंकवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वरोजगार और लघु उद्योगों का विकास जिले की आर्थिक मजबूती का आधार है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रघुवर सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

15 दिनों में कराएं शहरी आवास योजना के फ्लैट्स का गृह प्रवेश : डीसी

मेदिनीनगर : डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को जिले के विभिन्न नगर निकायों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अघोर आश्रम में शहरी आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैट्स से जुड़ी सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर 15 दिनों के भीतर लाभुकों का गृह प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए। समाहरणालय में आयोजित बैठक में मेदिनीनगर नगर निगम सहित छत्तरपुर, हुसैनाबाद और हरिहरगंज नगर पंचायतों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीसी ने जुडको द्वारा संचालित परियोजनाओं, शहरी जलापूर्ति योजना और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति की जानकारी ली तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वार्ड-23 में बन रहे इंडोर स्टेडियम, बस व ऑटो स्टैंड के लिए भूमि उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, होल्डिंग एवं प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तथा पार्क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों को जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पाटन प्रखंड कार्यालय परिसर में जल्द खुलेगा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र : बीडीओ

बंशीधर न्यूज

मेदिनीनगर : पलामू जिला स्तरीय टीम ने पाटन प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रस्तावित सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए उपलब्ध भवन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि इस माह के अंत तक प्रखंड कार्यालय परिसर में सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने की योजना है। बीडीओ अमित कुमार झा ने कहा कि प्रखंड कार्यालय परिसर में सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र खुलने से क्षेत्र की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी तथा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि जिला टीम द्वारा केंद्र संचालन से संबंधित सभी पहलुओं का निरीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र के खुलने से स्थानीय महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण मिलेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

हाइवे, फ्लाईओवर और रेलवे स्टेशन पर रील बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक : शर्मिला वर्मा

मेदिनीनगर : सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की होड़ में युवाओं द्वारा खतरनाक स्थानों पर रील और स्टंट वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। यह न केवल उनकी जान के लिए खतरा है, बल्कि आम लोगों और यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर रही है। यह बातें वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव शर्मिला वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर रुककर वीडियो बनाना, डांस करना या स्टंट करना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने जैसा है। कई बार रील बनाने वाले अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को आपात स्थिति में ब्रेक लगाना पड़ता है और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। शर्मिला वर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों के आसपास वीडियो बनाना भी बेहद खतरनाक है, जहां एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ट्रस्ट ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हाइवे, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

झामुमो नेता ताहीर अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, भवनाथपुर की समस्याओं से कराया अवगत

श्री बंशीधर नगर : झामुमो के केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य ताहिर अंसारी ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मूलभूत समस्याओं एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा। ताहिर अंसारी ने सीएम से क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी देते हुये शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कई आवश्यक विकास कार्य लंबित हैं, जिन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने ताहिर अंसारी द्वारा उठाये गये मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुये संबंधित समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों एवं क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा आवश्यक पहल कर समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा। मुलाकात के बाद ताहिर अंसारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है तथा उन्हें विश्वास है कि सरकार के सहयोग से भवनाथपुर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

मकरी पंचायत में पंचायत सेवक पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने बीडीओ से की शिकायत

भवनाथपुर : प्रखंड अंतर्गत मकरी पंचायत में पंचायत सेवक संजीव ठाकुर के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत सेवक पर अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज करने तथा योजनाओं में कार्य कराने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाते हुये बीडीओ को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण अभिषेक कुमार, संतोष यादव, हृदयानंद यादव, मनोज यादव, रामराज तिर्की, विजय उरांव, रवीन्द्र साह, मनोज कुमार यादव, शशिकांत विश्वकर्मा, इंदल साह, संतोष कोरवा, सुजीत कुमार, अजीत कुमार समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि पंचायत सेवक द्वारा मनरेगा योजना में केवल चुनिंदा लोगों का ही डिमांड लगाया जाता है। उनका आरोप है कि टीसीबी और मेड़बंदी जैसी योजनाओं में काम करने के बावजूद उनका डिमांड नहीं लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे डिमांड लगवाने या भुगतान से संबंधित जानकारी लेने पंचायत सेवक के पास जाते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है। विरोध करने पर पंचायत सेवक कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करते हैं। उधर पंचायत सेवक संजीव ठाकुर ने अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में यहां पदस्थापित हुये हैं और अभी सभी लोगों से उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का भुगतान एवं डिमांड संबंधित अभिलेखों, रिकॉर्ड और एमबी के आधार पर ही किया जाता है। बिना कार्य सत्यापन के भुगतान संभव नहीं है।

बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

भगवान बिरसा मुंडा को बताया प्रेरणास्रोत

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : झामुमो जिला समिति गढ़वा के तत्वावधान में मंगलवार को बिरसा मुंडा पार्क में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षमय जीवन, सामाजिक चेतना और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिये किये गये ऐतिहासिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिये प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिये संघर्ष करते हुये सामाजिक न्याय और स्वाभिमान की अलख जगाई थी। नेताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार और आदर्श झारखंड की पहचान एवं स्वाभिमान का आधार हैं। उनके बताये रास्ते पर चलकर ही समाज में समानता, न्याय और अधिकार की भावना को मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान उपस्थित नेताओं एवं कार्यकताओं ने उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिये कार्य करने का संकल्प दोहराया। श्रद्धांजलि सभा में झामुमो के केंद्रीय सदस्य तनवीर खान, मनोज ठाकुर और मनोज तिवारी ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, त्याग और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष शंभू राम, सचिव शरीफ अंसारी, संजय सिंह छोटू, कोषाध्यक्ष चंदन जायसवाल, गढ़वा प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अंसारी, ओमप्रकाश गुप्ता, मनीष कमलापुरी, दिलीप गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अल्प आयु में ही बिरसा मुंडा ने साहस और संघर्ष के बल पर धरती आबा का दर्जा प्राप्त किया : रघुराई राम

धरती आबा के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

बंशीधर न्यूज

मेराल : सामाजिक परिवर्तन केन्द्र के तत्वावधान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर संगवरिया स्थित निलाम्बर-पिताम्बर चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चन्द्रिका सिंह खरवार ने की। कार्यक्रम की शुरूआत गढ़वा जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रघुराई राम,पूर्व जिला परिषद सदस्य वीरेन्द्र साव, शिक्षक भरदूल राम ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। उस मौके पर रघुराई राम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, त्याग और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में ही बिरसा मुंडा ने अपने साहस और संघर्ष के बल पर जननायक के रूप में पहचान बनाई तथा धरती आबा और भगवान का दर्जा प्राप्त किया। उन्होंने आदिवासी अस्मिता, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज को उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। सभा के अंत में उपस्थित लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के बताये मार्ग पर चलने तथा सामाजिक एकता एवं जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन युवा नेता कुन्दन कुमार चंद्रवंशी ने किया। सभा में शिक्षक मनी सिंह, सुभाष कुमार रवि, सुबेश्वर राम, बसपा प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर राम, संजय राम, अम्बिका सिंह, अमित कुमार, बुद्धप्रिय रंजन, जय प्रकाश कुमार, कर्मदेव राम, रामबली पासवान, चंदेश्वर सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।

न्यूज अपडेट्स

मध्य विद्यालय रजवाडीह में किचेन का ताला तोड़ दो गैस सिलिंडर ले उड़े

मेदिनीनगर : सदर प्रखंड अंतर्गत रजवाडीह मध्य विद्यालय में अज्ञात चोरों ने विद्यालय के किचेन का ताला तोड़कर दो गैस सिलिंडर चोरी कर लिए। वहीं विद्यालय के कार्यालय का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक परशुराम तिवारी ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, बसौरा के इंजीनियरों का ग्रास रूट इंटर्नशीप कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर वह सुबह करीब 7:30 बजे विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कार्यालय का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बाद विद्यालय परिसर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि रसोईघर का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखे दो गैस सिलिंडर गायब हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि मामले की लिखित शिकायत सदर थाना प्रभारी को सौंप दी गई है। साथ ही इसकी सूचना डीएसई तथा रजवाडीह पंचायत के मुखिया को भी दे दी गई है।

पाटन पुलिस ने 300 किलो जावा महुआ व महुआ शराब किया नष्ट

मेदिनीनगर : पाटन पुलिस ने अवैध महुआ शराब के निर्माण और कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए थाना क्षेत्र के सिरमा एवं कुंड़वा गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 300 किलोग्राम जावा महुआ तथा तैयार महुआ शराब को बरामद कर मौके पर ही विनष्ट कर दिया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व पाटन थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने किया।

गढ़वा

डॉ संध्या पूरेचा के विचारों से प्रेरित गढ़वा के कला साधक

सांस्कृतिक साधना को नई दिशा देने का संकल्प

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : गढ़वा के कला साधक कला को विशिष्ठ पहचान देने वाली राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की कला साधिका डॉ संध्या पूरेचा के मार्गदर्शन को आत्मसात करने की कसौटी पर खरे उतरना चाहते हैं। इसके लिये वे कला को स्वर्णिम आयाम देने सरीखे डॉ पुरेचा के प्रयासों और उपलब्धियों की चर्चा-परिचर्चा में जुट गये हैं।

कौन हैं डॉ संध्या पूरेचा

भारतीय सांस्कृतिक जगत में डॉ संध्या पूरेचा एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कला को केवल मंचीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना के सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया है। प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्यांगना, शोधकर्ता, लेखिका और वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष के रूप में वे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु निरंतर सक्रिय हैं। डॉ पूरेचा की सांस्कृतिक सोच का केंद्र है साधना। उनके अनुसार कला केवल अभ्यास नहीं, बल्कि समर्पण, अनुशासन, ज्ञान और उत्कृष्टता की सतत यात्रा है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने भारतीय कला-जगत के भविष्य के लिये पांच महत्वपूर्ण स्तंभ निर्धारित किये हैं। जीवंत विरासत का संरक्षण, गुरु-शिष्य परंपरा का संवर्धन, शास्त्र और व्यवहार का समन्वय, विरासत-आधारित नवाचार तथा राष्ट्रीय पहचान के रूप में कला का सशक्तीकरण। मीट द आर्टिस्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने कलाकारों और संस्थाओं के बीच संवाद को नई दिशा दी है। उनका मानना है कि संस्कृति संग्रहालयों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और अभ्यास में जीवित रहती है। इसलिये परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परिचर्चा के दौरान संस्कार भारती झारखंड प्रांत के कला धरोहर संयोजक नीरज श्रीधर ने कहा कि डॉ संध्या पूरेचा के विचारों, कार्यशैली और सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रेरित होकर गढ़वा जिले के कला साधकों ने राष्ट्रहित में कुछ बड़ा और सकारात्मक करने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को जोड़ने वाली सशक्त शक्ति है। डॉ पूरेचा की साधना अवधारणा भारतीय संस्कृति को उसकी जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य की ओर अग्रसर करने वाला एक दूरदर्शी सांस्कृतिक मंत्र है।

रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपित ने कोर्ट में किया सरेंडर

मेदिनीनगर। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपित मंटू सिंह ने मंगलवार सुबह पलामू सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस अब मंटू सिंह को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मंटू सिंह को रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 मई को रामपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस क्रम में गोली चलाए जाने से सिकंदर चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग जख्मी हुए थे। इस संबंध में 17 लोगों के खिलाफ नामजद, जबकि 25 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में मुख्य आरोपित मंटू सिंह ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया।

रामपुर गोलीकांड का मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर कई स्तरों पर आंदोलन किया जा चुका है। दोनों पक्षों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक

एसडीएम ने दूर की राजनीतिक नेताओं की भ्रांतियां

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : सदर एसडीएम सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संजय कुमार ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच उत्पन्न शंकाओं और भ्रांतियों का निराकरण करना था। बैठक में एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का सरल एवं सहज भाषा में उत्तर दिया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, नागरिकता संबंधी प्रावधानों, आवश्यक दस्तावेजों तथा मतदाता सत्यापन की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपने-अपने क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाने की अपील की। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं की अब तक मैपिंग नहीं हो पाई है, उनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जायेगा। ऐसे मतदाता संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैप किये गये और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में नागरिकता संबंधी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने साथ माता और पिता दोनों के नागरिकता अथवा जन्म संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एसडीएम ने बताया कि आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची भी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है, ताकि वे मतदाताओं को सही जानकारी दे सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र के साथ किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक दस्तावेज 29 जुलाई के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा किये जाएंगे। बैठक में पैरेंटल मैपिंग के नियमों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि मतदाता अपने माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी के साथ मैपिंग करा सकते हैं। हालांकि अन्य रिश्तेदारों के साथ मैपिंग मान्य नहीं होगी। बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रभात रंजन, बसपा के नंदा पासवान, भाजपा के जितेंद्र प्रसाद, आजसू के शंकर प्रताप विश्वकर्मा, झामुमो के शरीफ अंसारी तथा राजद के करीब अंसारी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक

मेदिनीनगर : झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगा। एनजीटी के निदेर्शों के अनुपालन में मॉनसून अवधि के दौरान पर्यावरण संरक्षण, नदी तंत्र के संतुलन तथा जलीय जीवों के प्रजनन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लागू किया जाता है। निर्धारित अवधि में राज्य की किसी भी नदी से बालू का खनन, परिवहन अथवा उठाव की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान पूर्व में जारी वैध चालान के आधार पर भी बालू उठाव नहीं किया जा सकेगा। सरकारी निर्देश के अनुसार प्रतिबंध अवधि में बालू के अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खनन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बालू कारोबारियों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों से निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है। मॉनसून समाप्त होने के बाद नियमानुसार बालू उठाव की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी।

यूको बैंक के ग्राहकों से केवाईसी अपडेट के नाम पर साईबर ठगी, मैनेजर ने एसपी से की जांच की मांग

गढ़वा : यूको बैंक गढ़वा शाखा के ग्राहकों से केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर फर्जी कॉल कर साईबर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में यूको बैंक के शाखा के प्रबंधक ऋषांत कुमार श्रीवास्तव ने एसपी को आवेदन देकर मामले की जांच तथा संबंधित मोबाईल नंबर की ट्रेसिंग कराने की मांग की है। शाखा प्रबंधक द्वारा दिये गये आवेदन में बताया गया है कि पिछले पांच-छह दिनों से मोबाईल नंबर 7061719294 से लगातार बैंक ग्राहकों को कॉल किया जा रहा है। कॉल करने वाला व्यक्ति स्वयं को यूको बैंक गढ़वा शाखा का प्रबंधक बताकर ग्राहकों से केवाईसी अपडेट कराने के लिये व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय विवरण साझा करने का दबाव बना रहा है। आवेदन के अनुसार अब तक लगभग 20 ग्राहक इस संबंध में जानकारी लेने के लिये शाखा पहुंच चुके हैं। वहीं दो से तीन ग्राहक साईबर ठगी का शिकार भी हो चुके हैं तथा उन्होंने फर्जी कॉल प्राप्त होने के बाद उनके खातों से अनाधिकृत वित्तीय लेन-देन की शिकायत की है। शाखा प्रबंधक ने कहा है कि ठग बैंक के नाम का दुरुपयोग कर ग्राहकों में भ्रम और भय का माहौल बना रहे हैं, जिससे बैंक की साख और ग्राहकों का विश्वास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह एक सुनियोजित साईबर अपराध है, जो बैंक और उसके ग्राहकों को निशाना बनाकर संचालित किया जा रहा है। यूको बैंक प्रबंधन ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुये मोबाईल नंबर की ट्रेसिंग कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी एवं साईबर अपराध संबंधी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आम लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, नेट बैंकिंग पासवर्ड या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बैंक कभी भी फोन पर इस प्रकार की जानकारी नहीं मांगता है।

राशन वितरण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला प्रकाश में

कांडी : प्रखंड के अंतर्गत ग्राम मझिगावां टोला भेलवाखांड़ी में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन वितरण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। डीलर शारदा देवी (लक्ष्मी महिला विकास समिति जन वितरण दुकानदार) की मनमानी और अड़ियल रवैये से तंग आकर समस्त कार्डधारियों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने एमओ मुकेश त्रिपाठी एवं शाहिद अंसारी का घेराव किया और उन्हें एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। सौंपे गये शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुये कहा कि शारदा देवी द्वारा राशन वितरण में घोर लापरवाही और मनमानी की जा रही है। डीलर ने अब तक दो बार लाभुकों के हिस्से का सरकारी अनाज अपने निजी कार्यों में गमन (खर्च) कर दिया है। इस बड़ी धांधली के कारण गांव के लगभग 150 से अधिक राशन कार्डधारक परिवार अपने हक के सरकारी अनाज से पूरी तरह वंचित हो गये हैं, जिससे गरीबों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डीलर की इस कार्यशैली से पूरे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। विरोध प्रदर्शन करने और एमओ का घेराव करने वालों में मुख्य रूप से आशा देवी, जसपतिया देवी, मनमतिया देवी, कपिल राम, विन्देश राम, करन कुमार, चरन कुमार, जगरनाथ राम, राम केवल राम, रामचन्द्र राम, विजय राम, चारी राम, मनिष चौबे, मुनि राम, शम्भु प्रजापति, मदन प्रजापति, अवधेश राम, सुभग प्रजापति, निरज कुमार, रामायन यादव, सुर्यकांत कुमार, बोधा यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लाभुक शामिल थे।

श्रद्धा कपूर की 'ईथा' की रिलीज डेट आई सामने

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ईथा' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। रिलीज डेट सामने आने के बाद से ही श्रद्धा के प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल है। अभिनेत्री को आखिरी बार सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी 'स्त्री 2' में देखा गया था, जिसके बाद दर्शक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, 'ईथा' 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निमार्ताओं को उम्मीद है कि त्योहार के दौरान फिल्म को पारिवारिक दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलेगा। फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अयूब भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। लक्ष्मण उतेकर इससे पहले विक्की कौशल अभिनीत सफल फिल्म 'छावा' का निर्देशन कर चुके हैं। 'ईथा' महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है। फिल्म उनके संघर्ष, कला और लोक संस्कृति में दिए गए योगदान को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करेगी। श्रद्धा कपूर इस चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आएंगी, जिसे लेकर दर्शकों और फिल्म उद्योग में पहले से ही काफी चर्चा है। मैडॉक फिल्म्स की यह महत्वाकांक्षी परियोजना इस साल की चर्चित फिल्मों में शामिल मानी जा रही है।

हुमा कुरैशी की 'बेबी डू डाई डू' का टीजर रिलीज

अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी नई फिल्म 'बेबी डू डाई डू' के साथ दर्शकों के सामने एक बिल्कुल अलग अंदाज में लौट रही हैं। यह क्राइम थ्रिलर 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में जारी फिल्म के टीजर में हुमा को एक गूंगी-बहरी महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसका अतीत रहस्यों और दर्द से भरा हुआ है। टीजर में उनका किरदार भारत की पहली देशी हिटवुमन के रूप में सामने आता है, जो अपनी लाल छतरी के जरिए दुश्मनों का सफाया करती नजर आती है। करीब 90 सेकंड के टीजर की शुरूआत एक लड़की की मौत की कहानी से होती है, जिसके बाद कहानी हुमा के रहस्यमयी किरदार पर केंद्रित हो जाती है। बाहरी रूप से मासूम दिखने वाली यह महिला भीतर से बेहद खतरनाक है। टीजर में उन्हें मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हुए और छेड़छाड़ करने वालों का सामना करते हुए दिखाया गया है। कहानी इस ओर संकेत करती है कि किसी दर्दनाक घटना के बाद वह हिटवुमन बनने का रास्ता चुनती है और अपनी जिंदगी की दिशा बदल देती है। यह फिल्म हुमा कुरैशी के करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए वह निमार्ता के रूप में भी अपनी नई पारी शुरू कर रही हैं। फिल्म का निर्माण उन्होंने अपने भाई साकिब सलीम के साथ मिलकर किया है। फिल्म में सीमा पाहवा, चंकी पांडे, सिकंदर खेर और विद्या मालवड़े भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

आकाश में दुर्लभ नजारा, एक साथ दिखे सौरमंडल के दो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति

भूमि विवादों के समाधान को लेकर प्रशासन की बड़ी पहल

हर माह लगेगा अंचल और थाना दिवस

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : जिले में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। डीसी सह जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर अब जिले के सभी अंचलों एवं थाना क्षेत्रों में प्रत्येक माह नियमित रूप से अंचल दिवस और थाना दिवस का आयोजन किया जायेगा। इसका उद्देश्य भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण एवं अतिक्रमण से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। जिला स्तर पर जनसुनवाई एवं जन शिकायत निवारण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि भूमि विवादों के समाधान में और अधिक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसी को देखते हुये यह संयुक्त आदेश जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह की 15 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में अंचल दिवस आयोजित किया जायेगा। यदि यह तिथि अवकाश के दिन पड़ती है तो एक दिन पूर्व कार्य दिवस में कार्यक्रम होगा। इसी तरह प्रत्येक माह की 30 तारीख को थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया जायेगा। दोनों कार्यक्रमों का संचालन संबंधित सीओ एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से करेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंचल दिवस एवं थाना दिवस किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होंगे। कार्यक्रम के दिन सभी संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इन बैठकों में भूमि विवाद एवं दखल-कब्जा, भूमि सीमांकन, लगान अद्यतन, नामांतरण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जायेगी। विवादित नामांतरण मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद ही कार्रवाई की जायेगी। वहीं अतिक्रमण की शिकायतों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा उत्तराधिकार एवं आपसी सहमति आधारित नामांतरण को बढ़ावा देने के लिये जनजागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा। सीओ प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

अंचल दिवस एवं थाना दिवस की निगरानी के लिये एसी को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। प्रत्येक आयोजन के बाद इसकी समीक्षा रिपोर्ट डीसी को सौंपी जायेगी। डीसी पशुपति नाथ मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये इन निर्धारित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। उन्होंने कहा कि यह पहल सुशासन को मजबूत करने और भूमि विवादों में कमी लाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगी।

डीसी के आदेश के बावजूद डंडई में चार रोजगार सेवक हड़ताल पर कायम

डंडई : गढ़वा जिले में हड़ताल पर गये मनरेगा कर्मियों को दो दिनों के भीतर कार्य पर लौटने का डीसी पशुपतिनाथ मिश्रा का निर्देश डंडई प्रखंड में बेअसर साबित होता दिख रहा है। आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी प्रखंड के चार रोजगार सेवक अब तक सेवा में वापस नहीं लौटे हैं। जानकारी के अनुसार कार्य पर नहीं लौटने वाले रोजगार सेवकों में अशोक राम, अनिल केरकेट्टा, बृजमोहन राम और विनय चौबे के नाम शामिल हैं। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इसके बावजूद अब तक इन कर्मियों का ड्यूटी पर नहीं लौटना प्रशासनिक निदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना जा रहा है। रोजगार सेवकों की अनुपस्थिति का सीधा असर डंडई प्रखंड में मनरेगा योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। कई विकास योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो गई है। वहीं मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजनाओं में देरी के कारण विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने और लंबित कार्यों को गति देने की मांग की है।

पीओके में प्रदर्शन और हिंसक झड़प, 12 की मौत, आसिम मुनीर के खिलाफ लगे नारे

मीरपुर/रावलाकोट (इस्लामाबाद)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में राजनीतिक अधिकारों और विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ते तनाव के बीच प्रतिबंधित संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के सशस्त्र कार्यकताओं और कानून प्रवर्तन एजेन्सी (एलईए) के बीच सोमवार को रावलाकोट में हुई हिंसक झड़प में 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 प्रदर्शनकारी और 4 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना और खासतौर पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर से नाराज थे और आसिम मुनीर दहशतगर्द है के नारे लगा रहे थे। पुंछ के आयुक्त सरदार वहीद खान ने पुष्टि की कि इस संघर्ष में कुल 12 लोगों की जान गई, जबकि दर्जनों सुरक्षा अधिकारी घायल हुए हैं। उनके अनुसार, प्रतिबंधित संगठन के सशस्त्र सदस्यों ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर सुरक्षा बलों पर हमला किया और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और उपद्रवी तत्वों से दूरी बनाए रखने की अपील की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, अधिकांश राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं और बाजार तथा व्यावसायिक केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। आजाद जम्मू-कश्मीर (एजेके) पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, गोलीबारी में 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए जबकि 20 से अधिक पुलिस और सुरक्षा अधिकारी घायल हुए हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एजेके सरकार ने 9 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले जेएएसी को आतंकवाद-निरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। जेएएसी पहले भी आर्थिक मुद्दों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करता रहा है। मई 2024 और सितंबर 2025 में हुए कुछ प्रदर्शनों के दौरान भी सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में लोगों की मौत हुई थी। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन के हिंसक कार्यकताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और अशांति फैलाने वालों को जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। जनता से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित संगठन या उसके सहयोगियों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग न लें और केवल सरकारी स्त्रोतों से जारी जानकारी पर भरोसा करें। पाकिस्तान में संसदीय मामलों के संघीय मंत्री तारिया फजल चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अधिकांश मांगें स्वीकार किए जाने के बावजूद यह समूह क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसने समूह से वार्ता की और समझौते के अधिकांश बिंदुओं को लागू किया। मीरपुर डिवीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन से कथित संबंध रखने वाले 91 लोगों को गिरफ्तार किया है। कामरान अली ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार, डंडे और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, यह हिंसा उस समय भड़की जब पीओके के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षित 12 सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और इन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला जेएएसी द्वारा 9 जून को प्रस्तावित बड़े विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आया है। संगठन लंबे समय से शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने और स्थानीय लोगों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है। संगठन का आरोप है कि शरणार्थियों का राजनीतिक प्रभाव आवश्यकता से अधिक है। वहीं, जेएएसी नेता शौकत नवाज मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में नरसंहार शुरू कर दिया है। उन्होंने समर्थकों से 9 जून की प्रस्तावित रैली में शामिल होने की अपील की थी।

अमेरिकी न्यायालय ने ट्रम्प के आदेश को बताया गैरकानूनी

एच-1बी वीजा के लिए नहीं देने होंगे एक लाख डालर

बोस्टन (वॉशिंगटन)। अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा आवेदन पर लगाए गए एक लाख डॉलर के शुल्क को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस अभियान के लिए एक झटका है जिसका मकसद इमिग्रेशन को सीमित करना और अमेरिकी कर्मचारियों की मांग को बढ़ाना था। इस फैसले को अमेरिकी टेक कंपनियों और हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मैसाचुसेट्स में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो टी. सोरोकिन ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि एच-1बी वीजा पर लगाया गया एक लाख डॉलर का शुल्क वास्तव में एक टैक्स था, जिसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। अदालत ने इस आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया। बोस्टन में अमेरिकी जिला जज लियो सोरोकिन ने यह फैसला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरलों द्वारा दायर मुकदमे पर सुनाया। राज्यों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा सितंबर में घोषित उस नीति को चुनौती दी थी जिसके तहत एच-1बी वीजा की फीस में भारी वृद्धि की गई थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह शुल्क विदेशी कर्मचारियों के प्रवेश को सीमित करने के लिए एक आर्थिक दंड के रूप में लगाया गया है। हालांकि अदालत ने इसे जुमार्ना नहीं बल्कि टैक्स माना और कहा कि ऐसा करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है।उल्लेखनीय है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम के तहत हर साल 65,000 वीजा दिए जाते हैं और इसके अलावा एडवांस्ड डिग्री वाले कर्मचारियों के लिए 20,000 वीजा तीन से छह साल के लिए मंजूर किए जाते हैं। ट्रंप के आदेश से पहले विदेशी कर्मचारी के लिए वीजा चाहने वाले नियोक्ता आम तौर पर अलग-अलग वजहों के आधार पर लगभग 2 हजार डालर से 5 हजार डालर तक की फीस देते थे। नई नीति के तहत इसे बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दिया गया था, जिससे आवेदन संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। एच-1बी वीजा का सबसे अधिक लाभ भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवर उठाते हैं। इसलिए अदालत के इस फैसले को भारतीयों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अमेरिकावासी भारतीयों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हाल के वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते उपयोग, टेक कंपनियों में छंटनी और कड़े इमिग्रेशन नियमों के कारण विदेशी कर्मचारियों की भर्ती प्रभावित हुई थी। कई भारतीय पेशेवरों की नौकरियां भी चली गई थीं।

प्रभात टुडे नेटवर्क के लिए राधेरमण चौबे द्वारा गुलाब मेमोरियल मार्केट श्री बंशीधर नगर गढ़वा झारखंड से प्रकाशित, प्रधान संपादक-धीरेन्द्र चौबे, संपादक-धर्मेन्द्र कुमार चौबे* फोन : 9471737671, web-www.banshidharnews.com-Email-prabhatodaynetwork@gmail.com, *समाचारों के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेदार (सभी वादों का निपटारा नगर ऊंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के अधीन होगा)